SHRI JAGESH DESAI: I am not allowed any supplementary for the last two sessions. (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Two sessions?

SHRI JAGESH DESAI: Yes, two sessions. (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: I will allow you tomorrow. (*Interruptions*)... I will do it tomorrow. (*Interruptions*)... I will do it tomorrow. Q. No. 104.

Manufacture of currency printing papers and specialised inks

*104. SHRI SUNIL BASU RAY:
SHRI RAMACHANDRAN PILLAI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Indian units are capable of manufacturing currency paper and specialised inks in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether at present Government are importing currency printing paper and specialised inks; and

(d) if so, what steps are being taken for indigenous production of these for saving foreign exchange?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Security Paper Mill, Hoshangabad, a unit under the administrative control of the Ministry of Finance, makes watermarked bank/currency note paper. The Unit meets about 60 per cent of the total requirement of bank/currency note paper. The balance requirement of about 40 per cent is met by imports. So far as security printing inks are concerned, the Ink Factory attached to Bank Note Press, Dewas, another unit under the administrative control of the Ministry of Finance, makes some of the several types of inks i.e. Off Set Printing Ink, Letter Press Printing Ink, Quick Setting Intaglio Ink with Interleaving Feeder required for printing of currency/bank notes. However, the Ink Factory cannot make Quick Setting Intaglio Ink without Interleaving Feeder because of technological reasons. Hence the requirement of about 300 MT per annum for Quick Setting Intaglio Ink without Interleaving Feeder is met by imports.

(d) Government is exploring possibi- of augmenting domestic production.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ramachandran Pillai.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: The hon. Minister replies that 60 per cent of our requirement is met by the Government-owned Hoshangabad unit. The balance requirement of 40 per cent is met by imports. According to my information, our import is mainly from a cartel—a cartel from U.K.—a monopoly which controls the South Asian markets. The raw material for currency paper is available in abundance in India. We also produce all the chemicals required for production of the currency paper. There are reports that some of the paper mills specialised in making security paper have made a proposal before the Government of India that they would set up a plant with a performance guarantee and hand over that to the Government or set up a joint-venture unit or set up a unit, public or private, willing to sell at a lower price than the prevailing international price. I would like to know from the hon. Minister whether the reports are true; if so, whether the Government has taken any decision on that.

डा० अबरार अहमद : सर, 60 परसेंट पेपर एस०पी०एम०होशंगाबाद की पेपर मिल में बनाया जाता है और बाकी 40 परसेंट हमारी जो जरूरत है वह इम्पोर्ट से पूरी होती है । माननीय सदस्य ने पूछा है कि हम जो 40 परसेंट पेपर इम्पोर्ट करते हैं, उसको हम अपने यहां ही बनायें तो इसके बारे में जो हमारे

रिसोर्सेज हैं उसके बारे में क्या कदम उठाये हैं। तो इसके बारे में यह प्रयास कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस पेपर को बनाने की मिल लगाई जाय। लेकिन इसके लिए सिक्योरिटी प्वाइंट बहुत इम्पार्टेंट है। हमने होम मिनिस्ट्री से इस बारे में जानकारी ली है कि क्या सेक्योरिटी प्वाइंट आफ व्यू से नोट बनाने की फैक्टरी हम प्राइवेट सेक्टर में लगा सकते हैं। तो इस संदर्भ में अभी होम मिनिस्ट्री का हमें जवाब मिला है, जिसमें उन्होंने यह सलाह दी है कि सेक्योरिटी प्वाइंट आफ व्यू से यह ठीक नहीं है। यह जो एस०पी०एम होशंगाबाद है, यहां जो हमारी कैपेसिटी थी वह 3400 मीट्रिक टन की थी। 1983 में हमने उसको मार्डनाइज करके उसकी कैपेसिटी 6 हजार मीट्रिक टन तक की है। लेकिन इसका एक कारण यह है कि हम उस कैपेसिटी के बराबर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए यह प्रयास है कि 1995-96 तक पूरी कैपेसिटी के साथ उत्पादन कर सकें, जिससे इस कमी को पूरा किया जा सके।

SHRI SURESH KALMADI: Good maiden reply. Sir, he has given a good maiden reply.

MR. CHAIRMAN: Yes, a good reply. Second supplementary.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, the hon. Minister has replied that we have no faith in our private sector... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, my second supplementray is this. The hon. Minister has replied that we have no faith in our private sector. We have faith only in multinationals.

AN HON. MEMBER: In U.K.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: There are reports that the Government of India had given in 1991 a letter of intent to a person who is an agent of a multinational cartel which controls the entire South Asian market. It is also reported that he had not made any attempt at all to instal the plant. There are reports that this move was an attempt to prevent others from venturing into local manufacture. I would like to know whether the reports are true; if so, whether the Government has taken any decision on that.

डा० अबरार अहमद : सर, माननीय सदस्य ने जो यह पूछा है कि प्राइवेट सेक्टर में हमें विश्वास नहीं है, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है और वह भी नोट बनाने के कागज के बारे में, उसके लिए गृह मंत्रालय से पूरी जांच करा लेना बहुत जरूरी है। जांच करा लेने का मतलब यह नहीं है कि हमें किसी पर विश्वास नहीं है। जो माननीय सदस्य ने दूसरी बात कही है तो हम खुद इसके लिए एक कंपनी से कागज खरीदते थे। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इसका अल्टरनेटिव भी हमारे पास हो और कोई दूसरी कंपनी भी हमें कागज देने वाली हो। इसके लिए हमने अभी टेंडर फ्लोट किये थे। पहले जो हमारी कंपनी थी "पेटिल" उसको हमने 80 परसेंट आर्डर दिये हैं और 20 परसेंट दूसरी कंपनी को देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इसके बारे में भी हमने सेक्योरिटी प्वाइंट आफ व्यू की पूरी जांच पड़ताल करवाई है। जब हम पूरे इन्श्योर हो जायेंगे कि वहां से कागज खरीदने में हम पूरे सुरक्षित हैं और किसी भी तरह से हम यदि यह मान लेंगे कि वहां से कागज लेने पर कोई असुरक्षा नहीं है, तभी हम आगे इस बारे में विचार करेंगे।

SHRI JAGESH DESAI: Very good answer.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : सभापति जी, मझे मंत्री महोदय से यह जानना है कि नोट छपने के बाद सेक्योरिटी का इंतजाम किया जाय, यह एक पहलू है लेकिन कागज लेने में या स्याही लेने में होम मिनिस्ट्री की सेक्योरिटी कहां खड़ी होती है? अगर ये चीजें कैमिकली साबित हो गई हैं, लेबोरटरी टेस्ट में इनका सही सार्थकता सिद्ध हो गई है जो कागज हम बना रहे हैं यदि वह हमारी आवश्यकताओं

की पूर्ति करता है तो यहां पर टेक्नोलोजिकल रिपोर्ट चाहिए या सिक्यरिटी फेक्टर चाहिए और अगर आपने यह जांच शुरू की है तो यह जांच कब से चल रही है तथा उसमें कितने दिन और लगेंगे ?

डा० अबरार अहमद : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत अनुभवी हैं। जहां तक आपने कागज की बात कही है उसमें नोट बनाने के कागज को लेने के पहले सुरक्षा की बात पर आपत्ति उठाई है, माननीय सभापति महोदय, यदि नोट बनाने का कागज आसानी से किसी दूसरे को भी उपलब्ध हो जाए तो आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि आगे की प्रक्रिया में भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं, कोई न कोई तरीका आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए सुरक्षा का पक्ष देखना बहुत जरूरी है। जहां तक आपने यह पूछा कि यह कब से विचार कर रहे हैं तो इसके गृह मंत्रालय को हमने लिखा था, अभी हाल ही में उनकी रिपोर्ट हमें मिली है। बाहर की एक कम्पनी से कागज लेने का मैंने जिक्र किया है कि 20 प्रतिशत हम दूसरी कम्पनी से लेना चाहते हैं। इसके लिए हमने दो सदस्यों की एक कमेटी वहां भेजी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वह रिपोर्ट प्रोसेस में है। जब रिपोर्ट पर सुरक्षा की दृष्टि से पूरा विचार कर लिया जाएगा तभी उस पर निर्णय लिया जाएगा।

SHRI SARADA MOHANTY: I want to know from the Minister as to what action has been taken by the Government regarding the proopsal made by the Padamjee Pulp and Paper Mills, Pune, for printing currency notes. It has been pending since 1988.

डा० अबरार अहमद : माननीय सभापति महोदय, प्रस्ताव तो कई प्रकार के आते हैं लेकिन वित्त मंत्रालय जब तक उनको अपने मापदंडों के अनरूप सही नहीं समझे तब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं।

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Mr. Chairman, Sir, I want to know, when security factor would be taken care at Hoshangabad Paper Mills, why it is being rejected by the Home Ministry in other cases? What are the reasons? If the security factor could not be posing a threat to the Hoshangabad Paper Mills, why not to the other Mills also? That is my question.

डा० अबरार अहमद : माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही यह बात कही है कि होशंगाबाद की जो हमारी मिल है उसका हमने 1983 में माडर्नाइजेशन कर के केपेसिटी बढ़ाई है। इसकी 3.4 हजार मीट्रिक टन की क्षमता थी जिसको बढ़ा कर हमने 6 हजार मीट्रिक टन किया है। लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिससे हमारे प्रोडक्शन 6 हजार मीट्रिक टन नहीं हो पाया है। हमारी जो आवश्यकता है वह भी 6 हजार मीट्रिक टन की है। हमारा प्रयास यह है कि होशंगाबाद की जो हमारी क्षमता है उसके मुताबिक हम 6 हजार मीट्रिक टन उत्पादन कर सकें। उसी के अनुसार 1995–96 तक यह लक्ष्य है कि हम उस क्षमता के मुताबिक अपना उत्पादन कर सकेंगे। इस ओर हम प्रयास कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Question No. 105.

*105. [*The questioner (Shrimati Chandrika Abhinandan Jain) was absent. For answer vide col.....infra*]

*106. [*The questioners (Chaturanan Mishra and Shri Gurudas Das Gupta) were absent. For answer vide col.....infra*]

*107. *The questioner (Dr. Murli Manohar Joshi) was absent. For answer vide col.....infra*]

Closure of India investment Centres

*108. SHRI E. BALANANDAN†

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether some of the India Investment Centres have since been closed as part of a worldwide cost cutting drive;

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri E. Balanandan.